आकाशवाणी शिमला

16.01.2026 / प्रादेशिक समाचार / 19:45बजे

मुख्य समाचार

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा–पिछले एक दशक में स्टार्टअप इंडिया मिशन से देश में आई नई क्रांति।
- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पीएम ई बस योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों को विशेष छूट प्रदान करने का केंद्र से किया आग्रह।
- राज्यपाल ने भारतीय लेखा परीक्षा सेवा के युवा अधिकारियों से कर्त्तव्यों के निर्वहन में दक्षता व पारदर्शिता लाने का किया आह्वान।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा–राज्य सरकार में आपसी तालमेल की कमी से प्रदेश की कार्यप्रणाली पूरी तरह चरमराई।
- प्रदेश लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष रामेश्वर ठाकुर ने कहा–परीक्षाओं में पारदर्शिता सहित समयबद्ध परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए आयोग प्रयासरत।

प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम महज एक योजना नहीं बल्कि एक इंद्रधनुषी दृष्टि है जो विभिन्न क्षेत्रों को नए अवसरों से जोड़ती है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया मिशन महज दस वर्षों में एक क्रांति बन गया है और इसने पूरे देश में एक नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दशक पहले भारत में 5 सौ से कम स्टार्टअप्स थे लेकिन अब इनकी संख्या बढकर दो लाख से अधिक हो गई है।

सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि पीएम ई–बस सेवा योजना के तहत पहाड़ी राज्यों को कोई छूट प्रदान नहीं की गई है, जिससे ई–बसों के संचालन में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को ये भी बताया कि पीएम ई–बस सेवा योजना के तहत हिमाचल के केवल शिमला शहर को शामिल किया गया है क्योंकि यह योजना दस लाख जनसंख्या वाले शहरों में ही लागू होती है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से पीएम ई–बस सेवा योजना के तहत पहाड़ी राज्यों को छूट प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से डीज़ल बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदल रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को प्रदेश की अन्य मांगों से भी अवगत करवाया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

राज्यपाल

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भारतीय लेखा व लेखा परीक्षा सेवा के युवा अधिकारियों से कर्त्तव्यों के निर्वहन में दक्षता और पारदर्शिता लाने का आह्वान किया है। राज्यपाल ने आज लोक भवन शिमला में भारतीय लेखा व लेखा परीक्षा सेवा 2025 बैच के परिविक्षाधीन अधिकारियों के साथ संवाद किया। उन्होंने लोक सेवा, जवाबदेही और शासन में सत्यनिष्ठा के महत्त्व पर अपने विचार साझा किए। शिव प्रताप शुक्ल ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाने और सार्वजनिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने में लेखा व लेखा परीक्षा सेवाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया।

उप मुख्यमंत्री

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज ऊजा जिला में हरोली विधानसभा क्षेत्र के पंजावर में 15 करोड़ 37 लाख रूपए की लागत से बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष क्षेत्र में करीब दो हजार 5 सौ करोड़ रूपए के विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। अग्निहोत्री ने कहा कि क्षेत्र में बेहतर यातायात सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सड़कों के व्यापक

नेटवर्क को और मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरोली के रोड़ा में 5 करोड़ रूपए की लागत से ऑटोमेटिक वाहन परीक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है।

जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार के भीतर आपसी तालमेल नहीं है जिससे प्रदेश की कार्यप्रणाली पूरी तरह चरमरा गई है। कुल्लू में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि नेतृत्व में अनुभव की कमी के कारण सरकार को अधिकारियों से काम लेना भी नहीं आ रहा है, जिसका सीधा असर प्रशासन और जनहित के कार्यों पर पड़ रहा है।

रामेश्वर ठाकुर

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रामेश्वर ठाकुर ने कहा है कि आयोग परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के साथ–साथ समयबद्ध परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी शिमला से बातचीत में आज उन्होंने कहा कि आयोग ने हाल ही में ली गई एच.ए.एस. की परीक्षा का परिणाम रिकार्ड 6 माह के भीतर घोषित किया है जो आयोग के इतिहास में पहली बार हुआ है।

रामेश्वर ठाकुर ने ये भी बताया कि आने वाले समय में आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में ए.आई. यानि कृत्रिम बुद्धिमता का समावेश किया जाएगा, ताकि प्रश्नपत्रों में पुनरावृति और पेपर लीक की समभावना न रहे।

जगत सिंह नेगी

राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश में बागवानी क्षेत्र में उत्पाद विपणन प्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए सहकारी समितियों का मज़बूत नेटवर्क तैयार किया जाएगा।

वे आज सोलन ज़िला के नौणी स्थित डॉक्टर वाई.एस. परमार बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। राजस्व मंत्री ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से न केवल उत्पाद का बेहतर मूल्य प्राप्त किया जा सकता है बल्कि विपणन अधोसंरचना को गांव–गांव तक पहुंचाया जा सकता है।

शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला से प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के दल को एक्सपोजर विजिट के लिए रवाना किया। यात्रा के दौरान बच्चों को चंडीगढ़, अमृतसर और वाघा बॉर्डर जैसे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक महत्व के स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक्स्पोज़र प्रदान करना है।

मुख्य समाचार एक बार फिर

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा–पिछले एक दशक में स्टार्टअप इंडिया मिशन से देश में आई नई क्रांति।
- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पीएम ई बस योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों को विशेष छूट प्रदान करने का केंद्र से किया आग्रह।
- राज्यपाल ने भारतीय लेखा परीक्षा सेवा के युवा अधिकारियों से कर्त्तव्यों के निर्वहन में दक्षता व पारदर्शिता लाने का किया आह्वान।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा–राज्य सरकार में आपसी तालमेल की कमी से प्रदेश की कार्यप्रणाली पूरी तरह चरमराई।
- प्रदेश लोकसेवा के अध्यक्ष रामेश्वर ठाकुर ने कहा–परीक्षाओं में पारदर्शिता सहित समयबद्ध परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए आयोग प्रयासरत।